RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 02

अंक : 002

दि. 02.05.2026,

शनिवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लद्दाख में विभिन्न डेयरी अवसंरचना एवं सहकारी पहलों का शिलान्यास और उद्घाटन किया

(एजेंसी)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज लद्दाख के लेह में केन्द्रशासित प्रदेश के लिए विभिन्न डेयरी अवसंरचना एवं सहकारी पहलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री श्री एस पी सिंह बघेल एवं श्री जॉर्ज कुरियन तथा लद्दाख के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिए गए सहकारिता मॉडल के तहत आज लद्दाख में ढेर सारे कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज करगिल जैसी ऊंची जगह पर 10 टीएलपीडी क्षमता वाले डेयरी प्लांट का शिलान्यास हुआ है, जिसकी क्षमता 10,000 लीटर दूध प्रतिदिन प्रोसेस करने की है। करगिल की महिलाएं डेयरी प्लांट के माध्यम से अपने जीवन में उजाला ला सकती हैं, परिवार की मदद कर सकती हैं और आत्मनिर्भर भी बना सकती हैं। श्री शाह ने कहा कि वे एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहाँ की महिलाओं ने ऐसी ही छोटी-छोटी डेयरियों के माध्यम से 1,25,000 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल किया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इतनी संभावना है कि यहां की महिलाएं अपने परिवार और बच्चों की अच्छी पढ़ाई-लिखाई में योगदान कर सकें। श्री शाह ने कहा कि 25 करोड़ की लागत से जिस नई परियोजना की शुरूआत होने जा रही है, वह निश्चित रूप से करगिल की माताओं-बहनों के लिए शुभंकर साबित होगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि लेह में पहले से काम कर रहे मिल्क प्लांट में प्रतिदिन उत्पादन की व्यवस्था शुरू हो रही है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि लद्दाख में आईटीबीपी और सेना बहुत बड़े खरीददार हैं। यहां सीमा पर 18,000 जवान रहते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आईटीबीपी और सेना की दूध, दही और पनीर की जरूरत इस प्लांट से पूरी होगी। श्री शाह ने कहा कि 45 लाख रुपए की लागत से एक मोबाइल प्रयोगशाला भी लॉन्च की गई है, जिससे दूध की क्वालिटी के रखरखाव में बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एंड्रॉइड आधारित अटउर ऐप का शुभारंभ भी हुआ है, जिससे हमारे दुग्ध उत्पादक पशुपालक पारदर्शिता के साथ अपने दूध का हिसाब-किताब एक ही ऐप पर देख पाएंगे। इससे दुग्ध उत्पादक पशुपालकों के मन में आत्मविश्वास भी जागृत होगा। उन्होंने कहा कि आज जिन पाँच पशुपालकों को पुरस्कृत किया गया वे करगिल और लेह के सभी पशुपालकों के लिए प्रेरणा का रूप हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि लद्दाख मिल्क फेडरेशन और मदर डेयरी ने एक समझौता किया है। इससे लद्दाख को देश के बाजार के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि लद्दाख के ऑर्गेनिक उत्पादों को दिल्ली का बड़ा बाजार मिलना चाहिए। श्री शाह ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) से आग्रह किया कि वह इसके लिए नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड को साथ लेकर एक त्रिपक्षीय एमओयू करें। उन्होंने कहा कि मदर डेयरी के प्रोडक्ट तो यहां बेचे ही जाएं, साथ ही मदर डेयरी अन्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से यहां के प्रोडक्ट की भी देश भर में मार्केटिंग की व्यवस्था करे।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि हम लद्दाख में डेयरी अवसंरचना का विस्तार करने जा रहे हैं। लेह में आने वाले दिनों में 70 करोड़ रुपए की लागत से 50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। वह लेह में बढ़ने वाली संभावनाओं का तो दोहन करेगा ही, साथ ही करगिल में लगाए जा रहे संयंत्र से दूध बढ़ने पर दोनों क्षेत्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यहां के मौसम के अनुरूप अच्छी नस्ल की गाय और भैंस उपलब्ध कराने का काम होगा। लगभग हर साल अच्छी नस्ल की 500 गाय और भैंसे यहां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख काफी ठंडा प्रदेश है, यहां ऑक्सीजन की भी कमी होती है। इसलिए रिसर्च करके यहाँ के मौसम में ढल सकने वाले पशु स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि आगामी 10 साल में पशुओं की संख्या में लगभग तीन गुनी बढ़ोतरी करने की योजना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। श्री शाह ने कहा कि लद्दाख मिल्क फेडरेशन और एनडीडीबी में समझौता होने के बाद यह नेटवर्क 28 गांवों तक पहुंचा है और लगभग 1700 दुग्ध उत्पादक इससे जुड़े हैं। उन्होंने एनडीडीबी के अध्यक्ष से कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गांवों में, जहां पशुपालन संभव हो, वहां एनडीडीबी की पहुँच होनी चाहिए और उन्हें इन सभी पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि यहाँ दैनिक दूध की खरीद लगभग 7000 किलोलीटर तक पहुंची है। इसे अगले चार साल में 21,000 किलोलीटर तक पहुंचाकर यहां के किसानों की समृद्धि के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज एक डेयरी प्लांट का उन्नयन और पुनरुद्धार भी किया गया। पांच टीएलडीपी से बढ़ाकर इसकी क्षमता 10 टीएलडीपी कर दी गई साथ ही सेना के साथ एमओयू से इसे निश्चित रूप से फायदा होगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के परिदृश्य में बहुत बड़ा बदलाव आया है।पशुपालन विभाग में कई क्रांतिकारी बदलाव आए हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि 2014-15 में भारत का कुल दूध उत्पादन 146 मिलियन टन था। आजादी से लेकर 2014-15 तक मतलब 70 साल में 146 मिलियन टन हुआ और 2014-15 से लेकर 2024-25 तक 146 मिलियन टन से बढ़कर 248 मिलियन टन हो गया। मतलब 70% वृद्धि केवल 10 साल में हुई और उसमें से 50% वृद्धि पिछले 5 साल में हुई है।उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 2013-14 में 307 ग्राम थी, जो अब 485 ग्राम हो गई है।

उन्होंने कहा कि देश भर में कुल 2,36,000 सहकारी समितियों और लगभग 2 करोड़ दूध उत्पादकों के माध्यम से भारत ने यह उपलब्धि प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल में 75,000 नई दूध समितियां बनाने का लक्ष्य रखा हैऔर 46,000 मौजूदा समितियों को आधुनिक व सक्षम बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 75,000 में से 21,000 नई समितियां बनाने का काम हो चुका है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि लद्दाख के प्रशासन से आग्रह है कि लद्दाख के हर गांव, जहां दूध उत्पादन और पशुपालन की संभावना है, का दोहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां पश्मीना, ऑर्गेनिक उत्पादों और शहद से संबंधित सहकारी संस्थाओं को भी सहकारिता विभागआने वाले दिनों में जमीन पर उतारेगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि लेह-लद्दाख और करगिल की बहुत पुरानी मांग थी कि इसे केन्द्र शासित प्रदेश(UT) बनाया जाए। UT बनाने की मांग का मूल कारण था कि यहां विकास नहीं होता था। गृह मंत्री ने कहा कि 2019 में लद्दाख को UT बनाने के बाद अब सात जिले और 193 पंचायतें हो गई हैं। पांच नए जिले — शाम, नुब्रा, चांगथांग, जास्कर और द्रास — हाल ही में अधिसूचित हुए हैं। यहां की स्थानीय भाषा को भी प्रशासन की भाषा बनाया गया है। भोगी, पुर्गी, ऊर्दू, हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2019 से पहले इस UT में 1,800 किलोमीटर सड़कें थीं, आज 4,040 किलोमीटर हो गई हैं। 19 पुल थे, आज 72 पुल बन चुके हैं। मोबाइल टावर 344 थे, आज 653 हो गए हैं। हेलीपैड 7 थे, आज 41 हो गए हैं। बर्फ हटाने वाली मशीनें पहले 7 थीं, आज 215 हैं। ग्रिड से जुड़े गांव 145 थे, आज 184 हो गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पहले 1,182 थे, आज 3,153 हो गए हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का फोकस लद्दाख पर रहा है और यहाँ ढेर सारे विकास के काम हुए हैं। श्री शाह ने कहा कि जोजिला दर्रा साल में 127 दिन बंद रहता था, इस बार सिर्फ 19 दिन बंद रहा। कारगिल-जांस्कर मार्ग 154 दिन बंद रहता था, वह सिर्फ 11 दिन बंद रहा। बर्फ हटाने वाली मशीनों और अन्य संरचनाओं के कारण बहुत बड़ा फर्क पड़ा है।जोजिला सुरंग का काम प्रगति पर है और सिंकुला सुरंग का काम शुरू हो चुका है। नया नागरिक हवाई अड्डा भी बनने का काम चालू हो गया है। VSAT कनेक्टिविटी सभी पंचायतों में कर दी गई है और 4G टावरों में परिवर्तन का महत्वपूर्ण काम भी हुआ है।

ईवीएम-बैलट बॉक्स के साथ नहीं होगी गड़बड़ी! क्यूआर कोड से होगी एंट्री, टीएमसी के आरोप पर चुनाव आयोग ने क्या कहा?

(एजेंसी)।

मतगणना से ठीक पहले चुनावी माहौल सिर्फ वोटों की गिनती तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल में स्ट्रॉन्गरूम को लेकर उठे सवाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौके पर मौजूदगी और चुनाव आयोग की नई सुरक्षा व्यवस्था ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस ने पोस्टल बैलट और स्ट्रॉन्गरूम की सुरक्षा पर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने साफ किया कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत चल रही है।

इसी बीच चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों (काउंटिंग सेंटर) की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब काउंटिंग सेंटर में एंट्री के लिए दफ उड्ढ्री आधारित फोटो पहचान पत्र लागू किया जा रहा है। यह नई व्यवस्था पहली बार 4 मई 2026 को होने वाली मतगणना में लागू होगी।

चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अब मतगणना केंद्रों पर पुराने ढर्रे से काम नहीं चलेगा। 4 मई 2026 को होने वाली असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधानसभा चुनाव की मतगणना के साथ ही यह नया नियम लागू हो जाएगा। इसके तहत चुनाव आयोग के एउक्ळएळ पोर्टल पर एक खास दफ कोड आधारित फोटो आईडी कार्ड मॉड्यूल तैयार किया गया है।

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 'थ्री-टियर' (तीन स्तरीय) सुरक्षा घेरा बनाया गया है। पहले और दूसरे घेरे पर चुनाव अधिकारी (RO) द्वारा जारी किए गए कार्ड की मैन्युअल चेकिंग होगी। असली खेल तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण घेरे में होगा। मतगणना हॉल के ठीक बाहर डिजिटल स्कैनर लगे होंगे। जब तक आपका QR कोड वहां मौजूद डेटा से मैच नहीं करेगा, तब तक गेट नहीं खुलेगा। यह नियम सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि उम्मीदवारों, उनके एजेंटों और तकनीकी स्टाफ के लिए भी अनिवार्य होगा।

श्री आशुतोष गोवारिकर को 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गोवा में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के 57वें संस्करण के लिए प्रख्यात फिल्म निमार्ता श्री आशुतोष गोवारिकर को महोत्सव निदेशक नियुक्त किया है।

श्री गोवारिकर एक प्रख्यात फिल्म निमार्ता हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा में विशिष्ट योगदान दिया है। आईएफएफआई के साथ उनका जुड़ाव कई दशकों से है, जो सिनेमाई कलाओं और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म संस्कृति के विकास के प्रति उनकी गहरी रुचि को दशार्ता है।

पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो बैरियर-रहित टोलिंग सिस्टम लॉन्च

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के सूरत-भरूच खंड पर स्थित चोरायासी टोल प्लाजा पर भारत की पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) बाधा रहित (बैरियर-लेस) टोलिंग प्रणाली के शुभारंभ की घोषणा की। यह अत्याधुनिक प्रणाली ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) और ऋछरळँ जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके, वाहनों को बिना रुके निर्बाध टोल संग्रह की सुविधा प्रदान करती है।

एमएलएफएफ की शुरूआत भारत के टोलिंग इकोसिस्टम के डिजिटलीकरण और वैश्विक मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में एक बड़ा मील का पत्थर है। इस प्रणाली से यात्रा के समय में काफी कमी आने, राजमार्गों पर भीड़ कम होने, ईंधन दक्षता में सुधार होने, वाहनों के उत्सर्जन में कमी आने और टोल संचालन में मानवीय हस्तक्षेप कम होने की उम्मीद है।

श्री गडकरी ने कहा कि बाधा रहित टोलिंग नागरिकों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' (जीवन सुगमता) को बढ़ाएगी और देशभर में माल और लॉजिस्टिक्स की तेज एवं अधिक कुशल आवाजाही सुनिश्चित कर 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार सुगमता) को बढ़ावा देगी। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, यह पहल विश्व स्तरीय, प्रौद्योगिकी-संचालित राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचा बनाने की सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दशार्ती है, जो कुशल, पारदर्शी और यात्रियों के अनुकूल है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्राइवेट स्कूलों को साफ बड़ी चेतावनी, जबरन किताब-यूनिफॉर्म बेचने पर होगी कार्रवाई

(एजेंसी)।

दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर लंबे समय से उठ रही शिकायतों के बीच अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। राजधानी में कई अभिभावक लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि स्कूल उन्हें तय दुकानों से किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। इन शिकायतों के बाद अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निजी स्कूलों को सीधी चेतावनी दी है।

मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि किसी भी स्कूल को अभिभावकों पर किसी एक दुकान से सामान खरीदने का दबाव बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर सरकारी नियंत्रण यानी टेकओवर जैसे विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के हर निजी स्कूल को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि माता-पिता अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी खरीद सकते हैं। स्कूल किसी भी तरह की बाध्यता नहीं बना सकते।

उन्होंने निर्देश दिया कि यह जानकारी हर स्कूल अपने नोटिस बोर्ड, आधिकारिक वेबसाइट और स्कूल से जुड़े स्टोर पर साफ तौर पर प्रदर्शित करे। इसका उद्देश्य अभिभावकों को यह भरोसा देना है कि खरीदारी का फैसला उनका अपना होगा।

सरकार का मानना है कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह कदम जरूरी है, क्योंकि कई मामलों में अभिभावकों को सीमित विकल्प दिए जाते थे और अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि अब दिल्ली का कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी नहीं चला पाएगा। स्कूलों को अब यह बात अपने नोटिस बोर्ड, आधिकारिक वेबसाइट और स्कूल परिसर के भीतर चलने वाली दुकानों पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखनी होगी कि "अभिभावक कहीं से भी सामान खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं।"

अक्सर स्कूल किसी एक वेंडर से सांठगांठ कर लेते हैं और वहां सामान की कीमतें बाजार से काफी ज्यादा होती हैं। इसे 'कैप्टिव बाइंग' यानी मजबूरी में की गई खरीदारी कहा जाता है।

सीएम ने इस प्रथा को पूरी तरह से गैर-कानूनी बताते हुए कहा है कि 'सिंगल-वेंडर' का नियम अब नहीं चलेगा। हर स्कूल को बिना किसी अपवाद के इस आदेश का पालन करना होगा। अगर कोई स्कूल ऐसा नहीं करता है, तो इसे सीधे तौर पर सरकार के आदेश की अवहेलना माना जाएगा।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के 'घुसपैठियों' को वापस भेजने के संबंध में बयान से हिला ढाका! बांग्लादेश ने भारतीय दूत को किया तलब

(एजेंसी)।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा 'घुसपैठियों' को वापस भेजने के संबंध में दिए गए एक बयान पर ढाका ने सख्त आपत्ति जताई है। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने भारतीय कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बढे को तलब कर अपनी नाराजगी व्यक्त की।

बांग्लादेश का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी दोनों देशों के मधुर द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक हो सकती है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर सीमा सुरक्षा और प्रवासन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर दोनों पड़ोसियों के बीच संवाद की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय कार्यवाहक उच्चायुक्त को बुलाकर अपना कड़ा रुख स्पष्ट किया। महानिदेशक इशरत जहां ने इस बैठक में ढाका का आधिकारिक पक्ष रखा। बांग्लादेश ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की टिप्पणियाँ आपसी रिश्तों में दरार डाल सकती हैं। हालांकि मंत्रालय ने कोई औपचारिक लिखित बयान जारी नहीं किया, लेकिन कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार, भारत को यह संदेश दे दिया गया है कि भविष्य में ऐसे संवेदनशील विषयों पर बयान देते समय संयम और दूरदर्शिता बरतना आवश्यक है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म '' पर एक पोस्ट साझा की थी। उन्होंने बताया कि असम में 20 विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया और उन्हें वापस बांग्लादेश की सीमा में भेज दिया गया। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि "असभ्य लोग नरम भाषा नहीं समझते।" उन्होंने इन व्यक्तियों को 'अवैध बांग्लादेशी' करार दिया। उनके इस आक्रामक लहजे और 'पुश-बैक' की कार्रवाई के सार्वजनिक प्रचार ने ही बांग्लादेश सरकार को कड़ा रुख अपनाने पर मजबूर किया।

बांग्लादेश ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और बांग्लादेश साझा इतिहास और संस्कृति से जुड़े हुए पड़ोसी हैं। ऐसे में सार्वजनिक रूप से दिए गए अपमानजनक बयान आपसी विश्वास को ठेस पहुँचाते हैं। ढाका के अनुसार, ऐसे बयान न केवल नकारात्मक माहौल बनाते हैं, बल्कि जटिल द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर सहयोग जारी है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए कूटनीतिक गरिमा बनाए रखना अनिवार्य है।

इस विवाद के केंद्र में सीमा प्रबंधन और अवैध प्रवासन का पुराना मुद्दा है। बांग्लादेश ने भारत से आग्रह किया है कि संवेदनशील मामलों को सीधे संवाद के जरिए सुलझाया जाना चाहिए न कि सोशल मीडिया के जरिए। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों को एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे गलतफहमियां कम हों। वर्तमान स्थिति में दोनों पक्षों के लिए यह जरूरी है कि वे भावनाओं के बजाय कूटनीतिक प्रोटोकॉल को प्राथमिकता दें ताकि दक्षिण एशिया की स्थिरता और मित्रता बनी रहे।

सम्पादकीय

पाकिस्तान की धूर्तता

पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने का अभिनय तो कर ही रहा है साथ ही वह अमेरिका के होर्मुज समुद्री मार्ग में ईरान की नाकेबंदी से बचने के लिए तेहरान को 6 रास्ते दे दिए हैं ताकि वह अपना कच्चा तेल रूस और चीन को निर्बाध आपूर्ति कर सके। अब यदि ईरान के टैंकरों को अमेरिका की नाकेबन्दी का विकल्प मिल जाए तो भला ईरान क्यों झुकेगा। वह तो अमेरिकी दबाव का तमाशा बनाते हुए अपने तेल का निर्यात करेगा। दरअसल पाकिस्तान के कपटपूर्ण मैत्री का भण्डाफोड़ अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ डेरेक जी ग्रासमैन ने किया है। उन्होंने अमेरिका के ट्रंप प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को जमीन के रास्ते मार्ग उपलब्ध कराकर पाकिस्तान ट्रंप की "अधिकतम दबाव" वाली रणनीति को कमजोर कर रहा है। ग्रासमैन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा "ट्रंप प्रशासन आपके सामने एक समस्या है। आपका अच्छा दोस्त पाकिस्तान, ऐसा लगता है कि उसने अभी-अभी ईरान के लिए जमीन के रास्ते 6 मार्ग खोल दिए हैं। इससे ईरान की सरकार को होर्मुज में आपकी नाकेबंदी से बचने में मदद मिलेगी। इससे ईरान को अमेरिकी दबाव का सामना करते रहने में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद एक बार फिर अमेरिका के साथ दोहरा खेल खेल रहा है।" पाकिस्तान को इस बात की कभी कोई परवाह नहीं रही कि उसे विश्व बिरादरी में किस दृष्टि से देख जा रहा है। एक तरफ वह ईरान के तेलों को चीन और रूस तक पहुंचाने के लिए अमेरिकी नाकेबन्दी को नाकाम करने में जुटा है तो दूसरी तरफ ईरान के दशतेस्तान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एवं ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता ईब्राहिम रजाई ने एक तरफ तो इस्लामाबाद को अच्छा दोस्त बताया है लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि "वह मध्यस्थ के तौर पर उपयुक्त नहीं है।" रजाई ने यह खुलेआम आरोप लगाया कि पाकिस्तान पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है और अमेरिकी हितों को ज्यादा तरजीह देता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सुरक्षा विशेषज्ञ ग्रासमैन पाकिस्तान के इस दोहरे खेल को जान सकते हैं तो क्या अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी इस वास्तविकता से अनिभिज्ञ है? कदापि नहीं, अमेरिका को ईरान एवं खाड़ी देशों में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी सीक्रेट एजेंसियां विस्तार से उपलब्ध कराती हैं। इस वक्त तो अमेरिका इतना घबराया हुआ है कि वह अपनी इज्जत बचाने के लिए सब वुछ करने को तैयार है जिसकी उसे कीमत न चुकानी पड़े क्योंकि अमेरिका को इस बात का एहसास हो चुका है कि जो दोस्त उन्होंने पाकिस्तान के रूप में चुना है, वह 'मक्कारी' का मास्टर माना जाता है। उसने अमेरिका से अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ लड़ने के नाम पर करोड़ों डालर ऐंठ लिया किन्तु उस वक्त उसने तालिबानी संगठनों को यह कहकर हथियार आपूर्ति नहीं की कि पाकिस्तान आमी तो अमेरिकी हथियारों को चलाने में काफी माहिर है। किन्तु तालिबानियों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक हथियारों के लिए जो अमेरिका से राशि लेता था उससे तो वह अपनी सेना को मजबूत करता था जबकि अमेरिका से भी धन भी ऐंठता था और एहसान भी जताता था कि उसने तो मुस्लिम देश के खिलाफ ही अपनी सेना भेजी है। इस तरह वह अमेरिका के लिए मीठा भी बना रहा तो वहीं दूसरी तरफ उसी को धोखा भी देता रहा। 2016 में ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान की कपटपूर्ण वूटनीति को समझकर उसको दिए जाने वाले सारे अनुदानों को बन्द कर दिया था। किन्तु दोबारा सत्ता में आते ही राष्ट्रपति ट्रंप पर फिर पाकिस्तान प्रेम का बुखार चढ़ा। अब जब खुद उन्हीं के देश को अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने की चुनौती खड़ी है तो वह उस पाकिस्तान पर आंख मूंदकर भरोसा करते दिखे जो आदतन दोहरे चरित्र का देश है और इसके नेता आदतन झूठे और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मित्रता की सौदेबाजी करने के लिए वुख्यात हैं।

भारत को हिंद महासागर का 'रक्षक' बनाना चाहता है जापान, पहली बार दिया अभूतपूर्व ऑफर, निशाने पर चीन

जापान ने भारतीय नौसेना को मोगामी क्लास के महाशक्तिशाली युद्धपोत का ऑफर दिया है। यह युद्धपोत सबमरीन का शिकार करने में माहिर है। चीन के बढ़ते खतरे के बीच जापान ने पहली बार यह बड़ा कदम उठाया है जो भारत की ताकत को बढ़ाएगा।

टोक्योः (एजेंसी)। जापान की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत को मोगामी क्लास के युद्धपोत का ऑफर दिया है। जापान चाहता है कि उसकी तकनीकी मदद से भारत इस 50 करोड़ डॉलर के युद्धपोत को खुद से बनाए। यही नहीं जापान ने इस अपने सबसे घातक युद्धपोत को ऑस्ट्रेलिया को भी देना चाहता है। इन तीनों ही देशों का एक ही शत्रु है। वह है चीन। विश्लेषकों का कहना है कि अब तक रक्षात्मक रणनीति अपनाने वाला जापान अब खुलकर चीनी दादागिरी से निपटने में जुट गया है। इसी वजह से जापान ने भारत की नौसेना को यह अभूतपूर्व ऑफर दिया है। जापान चाहता है कि भारत हिंद महासागर में सुरक्षा मुहैया कराए। यही नहीं भारतीय नौसेना भी इस जापानी युद्धपोत की मुरीद है।

विश्लेषकों का कहना है कि अगर भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों ही इस मोगामी क्लास के युद्धपोत का इस्तेमाल करते हैं तो इससे वे एक-दूसरे के पोर्ट पर इन्हें मरम्मत भी आसानी से कर सकेंगे। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी ड्रैगन की नौसेना फुफकार रही है। चीन के युद्धपोत लगातार हिंद महासागर के रास्ते अफ्रीका के जिबूती तक चक्कर लगा रहे हैं। चीन की सबमरीन भी हिंद महासागर में आने लगी हैं। ऐसे में तीनों ही देशों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। यह वही इलाका है जहां से जापान का ज्यादातर तेल गुजरता है। साथ ही दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग मलक्का स्ट्रेट भी यही पर है।

भारत दे हिंद महासागर में सुरक्षा, जापान का प्लान

इससे भारत को यह फायदा होगा कि वह इस अत्याधुनिक युद्धपोत को अपने यहां बना सकेगा। इससे भारतीय नौसेना की ताकत इतना ज्यादा बढ़ जाएगी कि वह आसानी से हिंद महासागर में 'सुरक्षा देने वाली' हो जाएगी। जापान ने जो अपना ऑफर दिया है, उसमें मोगामी युद्धपोत का डिजाइन और उसे भारतीय शिपयार्ड में जापानी मटेरियल की मदद से बनाने में मदद करना शामिल है। एक मोगामी क्लास के युद्धपोत को बनाने में 50 करोड़ डॉलर का खर्च आएगा। इसे एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों तथा टारपीडो की मदद से लैस किया जा सकता है।

ऐसा पहली बार है जब जापान ने भारत को अपना कोई बहुत महत्वपूर्ण हथियार सिस्टम ऑफर किया है। वश्लेिषकों का कहना है कि यह ऑफर दिखाता है कि जापान रक्षा क्षेत्र में ज्यादा करीबी भागीदारी चाहता है। 21 अप्रैल को जापानी की कैबिनेट ने हथियारों के निर्यात और तकनीक को लेकर कड़े प्रतिबंधों को कम किया है। ऑस्ट्रेलिया के एडीलेड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पुर्णेंद्र जैन ने साऊथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से बातचीत में कहा कि सह निर्माण का समझौता पीएम मोदी के 'मेक इन इंडिया' अभियान से मेल खाता है। इसके जरिए भारत अपने घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ाना चाहता है।

भारत का इरादा वैश्विक बाजार में अपने सपायरों में विविधता लाने का है। साथ अपने सैन्य आधुनिकीकरण को तेज करने का है।

प्रोफेसर पुर्णेंद्र जैन ऑस्ट्रेलिया के एडीलेड यूनिवर्सिटी

रूस से निर्भरत को घटा रहा है भारत

रिपोर्ट के मुताबिक भारत चाहता है कि उसकी आयात पर से निर्भरता कम हो जाए। भारत अपनी रूस पर से भी निर्भरता को कम करना चाहता है और इसी वजह से उसने हाल के वर्षों में फ्रांस, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से हथियारों का आयात बढ़ा रहा है। जैन ने बताया कि अभी आधिकारिक रूप से जापान ने अपना पूरा ऑफर नहीं दिया है। जेएनयू में जापानी अध्ययन के प्रोफेसर स्राबनी रॉय चौधरी ने कहा कि भारत की तटीय रेखा बहुत लंबी है। भारत को बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक अपने तटों की सुरक्षा करनी होती है। यह जापान के मुक्त और स्वतंत्र हिंद प्रशांत की संकल्पना के हिसाब से प्रासंगिक है।

जापान के मोगामी युद्धपोत की ताकत को जानें

मोगामी क्लास फ्रीगेट खासतौर पर एंटी सबमरीन युद्धकौशल के लिए बनाए गया है

जापानी युद्धपोत दुश्मन की सबमरीन को ट्रैक करता है, उसका शिकार करता है और रोकता है

यह युद्धपोत स्टील्थ तकनीक से लैस है जिससे दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता है

मोगामी फ्रीगेट मल्टी मशिन युद्धपोत है जो हाई ऑटोमेशन के लिए डिजाइन किया गया है

जापानी युद्धपोत को चलाने के लिए केवल 90 नौसैनिकों की जरूरत होती है जो इसी तरह के युद्धपोत के लिए आधे से भी कम है

जापान और भारत दोनों मिलकर इसके वल्लूङ्ग१ल्ल रेडियो एंटेना को बनाने पर सहमत हुए हैं

जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्धपोत के लिए 6.5 अरब डॉलर का समझौता हुआ है

भारत का फलोदी सट्टा बाजार हुआ पुराना, अमेरिका के पॉलीमार्केट ने बंगाल चुनाव पर की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, आखिरी दौर में अचानक पलटा पासा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दो चरणों के बाद सट्टा बाजार में जबरदस्त हलचल है. अब तक चर्चा में रहने वाले फलोदी सट्टा बाजार को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका के प्रेडिक्शन मार्केट 'पॉलीमार्केट' (ढङ्ग'८ं१'ी३) ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं. इस अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर बंगाल चुनाव को लेकर करीब 4.8 मिलियन डॉलर का दांव लग चुका है.जानें किस पार्टी को दे रहे हैं सत्ता. पश्चिम बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, इसका फैसला तो चुनाव के नतीजे करेंगे, लेकिन सट्टा बाजार में अभी से बड़ा उलटफेर शुरू हो गया है. अब तक लोग केवल राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों पर नजर टिकाए बैठे थे, लेकिन इस बार बंगाल के दंगल में सात समंदर पार अमेरिका के 'पॉलीमार्केट' ने तहलका मचा दिया है. मीडिया में छपी खबर के मुताबिक, अमेरिकी प्रेडिक्शन मार्केट में बंगाल चुनाव पर 4.8 मिलियन डॉलर से ज्यादा की ट्रेडिंग हो चुकी है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दूसरे चरण के मतदान के बाद जीत-हार का पूरा गणित बदल गया है. जहाँ पहले ममता बनर्जी की टीएमसी को फेवरिट माना जा रहा था, वहीं अब विदेशी सट्टेबाज बीजेपी की जीत पर भारी दांव लगा रहे हैं. आंकड़ों की मानें तो बीजेपी की जीत की संभावना अब 56 फीसदी के पार निकल गई है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है.

पॉलीमार्केट में बंगाल चुनाव का ग्लोबल क्रेज

अमेरिकी प्रेडिक्शन मार्केट पॉलीमार्केट पर बंगाल चुनाव को लेकर हो रही ट्रेडिंग ने सबको हैरान कर दिया है. वियॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्लेटफॉर्म पर निवेशक सीधे तौर पर अपनी राय और पैसा लगा रहे हैं. 29 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, इस ऑनलाइन बाजार में करीब 4.8 मिलियन डॉलर का व्यापार बंगाल चुनाव के नतीजों पर हुआ है. यह पहली बार है जब किसी राज्य के चुनाव को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा आर्थिक दांव देखा जा रहा है. बाजार में बीजेपी की जीत की संभावना 56 प्रतिशत और टीएमसी की 43 प्रतिशत दिखाई जा रही है, जबकि अन्य दल 1 प्रतिशत से भी नीचे हैं.

दूसरे चरण के बाद ऐसे पलटी पूरी बाजी

इस चुनावी सट्टे में असली ट्विस्ट दूसरे चरण के मतदान के बाद आया है. अप्रैल की शुरूआत में इसी पॉलीमार्केट पर टीएमसी को 75-80 प्रतिशत के साथ सबसे मजबूत बताया जा रहा था, तब बीजेपी महज 20-25 प्रतिशत पर थी. लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद यह आंकड़ा 54 प्रतिशत पर पहुंचा और दूसरे चरण की हिंसा और भारी मतदान के बाद बीजेपी अब 56 प्रतिशत के साथ सबसे आगे निकल गई है. यह ट्रेंड बताता है कि जैसे-जैसे वोटिंग बढ़ रही है, सट्टेबाजों का भरोसा बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा है, जिसने बंगाल की सत्ता की लड़ाई को बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ा कर दिया है.

पॉलीमार्केट के डेटा का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि भले ही जीत की संभावना बीजेपी की ज्यादा दिख रही है, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम में टीएमसी अब भी काफी आगे है. रिपोर्ट के अनुसार, टीएमसी पर करीब 1.8 मिलियन डॉलर की ट्रेडिंग हुई है, जबकि बीजेपी पर यह आंकड़ा 1.1 मिलियन डॉलर है. विशेषज्ञों का मानना है कि टीएमसी पर ज्यादा वॉल्यूम होने का मतलब है कि कई लोग उसकी हार पर दांव लगा रहे हैं या फिर कुछ बड़े सट्टेबाज भारी रकम के साथ बाजार में उतार-चढ़ाव पैदा कर रहे हैं. यह विरोधाभास संकेत देता है कि बंगाल की जनता का मिजाज समझना इस बार सटोरियों के लिए भी टेढ़ी खीर है.

व्हेल ट्रेडर्स की एंट्री से मचा हड़कंप

सट्टा बाजार में 'व्हेल ट्रेडर्स' यानी उन बड़े खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है जो लाखों डॉलर एक साथ निवेश करते हैं. रिपोर्ट में 'ङ१ङ्ग२ल४ल्ल३ी१' नाम के एक प्रोफाइल का जिक्र है, जिसने बीजेपी की जीत के 'ी२' वाले 1,05,417 शेयर खरीदे हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि अकेले इस खिलाड़ी ने बीजेपी की जीत पर 44 हजार से 60 हजार डॉलर के बीच दांव लगाया है. जब कोई बड़ा निवेशक इतनी मोटी रकम लगाता है, तो बाजार का पूरा समीकरण बदल जाता है. इसी वजह से बीजेपी का जीत प्रतिशत अचानक बढ़ गया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर न्यूज रूम्स तक चर्चा गर्म है.

दिल्ली और फलोदी सट्टा बाजार के अलग दावे

एक तरफ जहाँ अमेरिकी बाजार बीजेपी की लहर दिखा रहा है, वहीं दिल्ली और फलोदी के सट्टा बाजारों के आंकड़े थोड़े अलग हैं. दिल्ली सट्टा बाजार के मुताबिक, टीएमसी को 146-149 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी 140-143 सीटों के साथ कड़ी टक्कर दे रही है. भारतीय बाजारों में अभी भी मुकाबला बराबरी का माना जा रहा है. वियॉन की रिपोर्ट कहती है कि यह अंतर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पॉलीमार्केट में कई विदेशी निवेशक और वीपीएन का इस्तेमाल करने वाले भारतीय शामिल हैं, जिनकी सोच स्थानीय सट्टा बाजारों से अलग हो सकती है.

भारी मतदान के बीच कानूनी पेच और सट्टा

बंगाल में पहले दो चरणों में जो मतदान हुआ है, उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. पहले चरण में 93.19% और दूसरे चरण में 91.41% वोटिंग ने विश्लेषकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. पॉलीमार्केट जैसे प्लेटफॉर्म भारत में कानूनी तौर पर पेचीदा हैं, फिर भी क्रिप्टो और स्टेबलकॉइन्स के जरिए लोग जमकर रिस्क ले रहे हैं. सट्टेबाजों को लग रहा है कि यह भारी वोटिंग सत्ता परिवर्तन का संकेत है, और यही वजह है कि आखिरी दौर के आते-आते सट्टा बाजार में जीत-हार का पूरा समीकरण ही बदल गया है.

क्या सट्टा बाजार की भविष्यवाणी सच होगी?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सात समंदर पार बैठे सट्टेबाजों की यह भविष्यवाणी सच साबित होगी? वियॉन में प्रकाशित इस खबर ने बंगाल की राजनीति में एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है. चुनाव के आखिरी चरणों तक यह आंकड़ा और भी बदल सकता है. लेकिन फिलहाल, पॉलीमार्केट के इस रुझान ने ममता बनर्जी के खेमे में चिंता और बीजेपी के खेमे में उत्साह पैदा कर दिया है. बंगाल का यह रण अब केवल बूथों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक वित्तीय बाजारों के दांव-पेंच का हिस्सा बन चुका है.

यह है हमारी अपनी हाइड्रोजन ट्रेन, दिल छू लेगी इसकी खासियत, पहली नजर में हो जाएगा इससे प्यार

(एजेंसी)।

हमारी अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल सफल रहा है. आज अपनी इस ट्रेन ने हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच रफ्तार भरी है. इस सफल ट्रायल के साथ हमारा देश भारत जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और चीन जैसे देशों की कतार में आ खड़ा हुआ है. हाइड्रोजन ट्रेन की इस सफलता के साथ भारत ने क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी की दिशा में नया कदम बढ़ा दिया है. क्योंकि, इस ट्रेन से न ही धुआं निकलता है और न ही प्रदूषण होता है. इससे सिर्फ पानी की भाप निकलता है. सबसे खासबात यह है कि इस ट्रेन के लिए विकसित की गई टेक्नोलॉजी पूरी तरह से अपनी है. भारत में हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, भारत में हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल, भारत में जीरो-एमिशन ट्रेन, ग्रीन

हाइड्रोजन ट्रेन, भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन ट्रेन, 'मेक इन इंडिया' ट्रेन, हाइड्रोजन फ़्यूल ट्रेन के फायदे, जींद-सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन

सबसे शक्तिशाली इंजन क्षमताः इस ट्रेन का इंजन भी बहुत ताकतवर है. इसकी कुल क्षमता 2400 किलोवाट यानी करीब 3200 हॉर्सपावर है. दोनों पावर कार मिलकर ट्रेन को अच्छी रफ्तार और ताकत देती हैं. इससे ट्रेन भारी लोड और ज्यादा यात्रियों के साथ भी आसानी से चल सकती है.

यह ट्रेन पर्यावरण के लिए बिल्कुल सुरक्षित है. इसमें हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जिससे धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती. सिर्फ पानी की भाप निकलती है, जो सेहत और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है.

इस ट्रेन का ट्रायल पूरी सुरक्षा के साथ किया गया. लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसे चलाकर देखा गया. ब्रेक, फ्यूल सिस्टम और बाकी सभी जरूरी चीजों की जांच की गई और सभी टेस्ट सफल रहे. सफल ट्रायल के बाद ग्रीन एनर्जी की तरफ भारत ने मजबूत कदम बढ़ा दिया है.

यह ट्रेन पूरी तरह भारत में बनी है. चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसे तैयार किया गया है. इसमें इस्तेमाल की गई तकनीक भी भारतीय इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है. यह 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत का बेहतरीन उदाहरण है.

इस हाइड्रोजन ट्रेन में एक साथ 2600 से ज्यादा यात्री सफर कर सकते हैं. इतनी बड़ी क्षमता इसे खास बनाती है. इससे ज्यादा लोगों को एक साथ सफर की सुविधा मिलेगी और भीड़भाड़ कम करने में भी मदद मिलेगी.

रितेश देशमुख का कमाल, छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनी फिल्म का चला जादू

फल्म- राजा शिवाजी

स्टारकास्ट- रितेश देशमुख, संजय दत्त, सलमान खान, अभिषेक बच्चन

डायरेक्टर- रितेश देशमुख

रनटाइम- 3 घंटे 6 मिनट

स्टार- 4 (****)

छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ इतिहास का नाम नहीं बल्कि एक ऐसी भावना हैं जो खासकर महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में गहराई से बसती है। इसी भावना को पर्दे पर उतारने का जिम्मा उठाया है बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख फ्ऱ्रीरँ ऊेरँ४ँ) ने और उन्होंने इसे सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि पूरी शिद्दत से जिया है।

'राजा शिवाजी' ने ऊंचा किया रितेश देशमुख का कद

फिल्म 'राजा शिवाजी' आज यानी 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म में रितेश देशमुख सिर्फ एक अभिनेता के रूप में ही नहीं बल्कि लेखक और निर्देशक के तौर पर भी अपनी अलग पहचान छोड़ते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने राजा शिवाजी जैसे प्रोजेक्ट के जरिए अपने ही कद को और ऊंचा कर लिया है।

क्या है फिल्म 'राजा शिवाजी' की कहानी?

-फिल्म की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, उनके संघर्ष और स्वराज के लिए लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाई को बारीकी से पेश करती है। मराठा और मुगल साम्राज्य के बीच की राजनीति को जिस तरह से दर्शार्या गया है, वह दर्शकों को उस दौर में ले जाता है।

-ये फिल्म सिर्फ युद्ध के दृश्य नहीं दिखाती बल्कि शिवाजी महाराज की सोच, उनकी रणनीति और उनके नेतृत्व की गहराई को सामने लाती है। खासतौर पर उनकी युद्ध नीति, जिसमें दुश्मन के मनोबल पर पहले वार करना शामिल था, को बेहद प्रभावी ढंग से फिल्माया गया है।

दमदार रिसर्च और इमोशन का मेल है ये फिल्म

-फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी गहरी रिसर्च और मजबूत लेखन है। हर किरदार को कहानी में सही जगह दी गई है और ये साफ झलकता है कि इस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की गई है।

-रितेश देशमुख ने निर्देशक के तौर पर खुद को चमकाने की बजाय फिल्म को चमकाने पर ध्यान दिया है, जो उनकी समझदारी को दशार्ता है। फिल्म में शिवाजी महाराज के जीवन के कई ऐसे पहलू दिखाए गए हैं, जिनसे शायद बहुत से लोग अनजान होंगे।

-हालांकि विजुअल इफेक्ट्स

(श्ऋ) कुछ जगहों पर और बेहतर हो सकते थे लेकिन कहानी की मजबूती और भावनात्मक जुड़ाव इन छोटी कमियों को नजरअंदाज करवा देता है।

फिल्म की दमदार स्टारकास्ट और उनकी एक्टिंग

-अभिनय के मामले में फिल्म बेहद मजबूत नजर आती है। रितेश देशमुख ने शिवाजी महाराज के किरदार को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाया है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और संवाद अदायगी किरदार के साथ पूरी तरह मेल खाती है। ये उनके करियर के बेहतरीन प्रदर्शन में से एक माना जा सकता है।

-सुपरस्टार सलमान खान का कैमियो फिल्म में एक अलग एनर्जी लेकर आता है। उनके स्क्रीन पर आते ही थिएटर में तालियों और सीटियों की गूंज सुनाई देती है।

-संजय दत्त अपने किरदार में बेहद प्रभावशाली नजर आते हैं। उनका खतरनाक अंदाज दर्शकों में गुस्सा और डर दोनों पैदा करता है, जो उनके अभिनय की सफलता है।

-अभिषेक बच्चन ने शिवाजी महाराज के बड़े भाई के किरदार में जान डाल दी है और लंबे समय बाद वह इतने प्रभावी लगे हैं। विद्या बालन ने भी अपने दमदार अभिनय से प्रभावित किया है। उनके किरदार की दृढ़ता और ताकत स्क्रीन पर साफ नजर आती है।

-इसके अलावा भाग्यश्री, जेनेलिया डिसूजा, अमोल गुप्ते, जितेंद्र जोशी, सचिन खेड़ेकर और बोमन ईरानी जैसे कलाकारों ने भी अपने-अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है।

राइटिंग और डायरेक्शनः फिल्म की असली ताकत

फिल्म की रीढ़ इसकी शानदार लेखनी है। रिसर्च और स्क्रिप्ट पर की गई मेहनत हर सीन में दिखाई देती है। निर्देशन के स्तर पर रितेश देशमुख ने कमाल कर दिया है। उन्होंने हर किरदार को संतुलित तरीके से पेश किया है और कहानी को प्रभावशाली बनाए रखा है। ये फिल्म उनके निर्देशन कौशल का बेहतरीन उदाहरण है।

म्यूजिकः अजय-अतुल का जादू

फिल्म का म्यूजिक अजय-अतुल (अ्रं८-अ३४') ने तैयार किया है, जो फिल्म की आत्मा बनकर उभरता है। बैकग्राउंड स्कोर और गानों में वो भावनात्मक ताकत है, जो कहानी को और प्रभावी बनाती है।

क्यों देखनी चाहिए फिल्म 'राजा शिवाजी'?

ये फिल्म सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसे महान योद्धा की कहानी, जिन्हें लोग भगवान के समान मानते हैं। अगर आप इतिहास, देशभक्ति और मजबूत कहानी वाली फिल्मों के शौकीन हैं, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक एहसास है जिसे बड़े पर्दे पर महसूस करना ही सही मायनों में इसका आनंद लेना है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

लखनऊः नारी आक्रोश यात्रा कल, हजरतगंज के इन हिस्सों में बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था; जानिए कहां होगी नो एंट्री

लखनऊ

नारी आक्रोश मशाल यात्रा के कारण शनिवार को हजरतगंज इलाके में यातायात बदला रहेगा। दिन में तीन बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक आवागमन में बदलाव किया गया है। इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस स्कूली वाहन, शव वाहन, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को निकलवाएगी।

– लाल बत्ती चौराहा की ओर से 1090 चौराहा, समतामूलक चौराहा, पॉलीटेक्निक चौराहा, सुभाष चौराहा चौक की ओर जाने वाला सामान्य यातायात हजरतगंज की ओर प्रतिबंधित रहेगा। यह लालबत्ती चौराहा से जी 20 चौराहा कमता तिराहा या कैंट होकर जाएगा।

– डीएसओ चौराहा, रॉयल होटल चौराहा की ओर से सिकंदरबाग चौराहा, महानगर, गोमतीनगर की ओर जाने वाला सामान्य यातायात हजरतगंज की ओर प्रतिबंधित रहेगा। यह लालबत्ती चौराहा से जी 20 चौराहा, कमता तिराहा होकर जाएगा।

– पार्क रोड की ओर से चारबाग, कैसरबाग, लालबत्ती की ओर जाने वाला सामान्य यातायात हजरतगंज चौराहा की ओर नहीं जा सकेगा। यह पार्क रोड से सिकंदरबाग चौराहा, चिरैयाझील चौराहा, सुभाष चौराहा की ओर से जाएगा।

– गोमतीनगर की ओर से कैंट, चारबाग, आलमबाग, चौक की ओर जाने वाला सामान्य यातायात हजरतगंज चौराहा की ओर नहीं जा सकेगा। यह यातायात समतामूलक चौराहा से ग्रीन कारिडोर होकर डालीगंज चौराहा होकर जा सकेगा।

– सिकंदरबाग चौराहा की ओर से चारबाग, चौक, कैसरबाग की ओर जाने वाला सामान्य यातायात हजरतगंज की ओर नहीं जा सकेगा। यह सुशीला स्मृतिका ग्रीन कॉरिडोर चौराहा होकर ग्रीन कारिडोर, डालीगंज चौराहा होकर जा सकेगा।

– परिवर्तन चौक, हिंदी संस्थान तिराहा की ओर से गोमतीनगर, कैंट, अर्जुनगंज, तेलीबाग कानपुर रोड की ओर जाने वाला सामान्य यातायात हजरतगंज चौराहा की ओर नहीं जा सकेगा। यह सुभाष चौराहा से ग्रीन कॉरिडोर या चिरैयाझील होकर जा सकेगा।

– तेलीबाग / बंगलाबाजार से गोमतीनगर / महानगर की ओर जाने वाला सामान्य यातायात डीएसओ चौराहा /हजतरगंज की ओर प्रतिबंधित रहेगा, बल्कि यह यातायात बन्दरियाबाग चौराहा / गोल्फ क्लब चौराहा / 1090 चौराहा / समतामूलक चौराहा होकर जा सकेगा।

– लालबाग चौराहा से महानगर, गोमतीनगर, कैंट की ओर जाने वाला सामान्य यातायात कैपिटल तिराहा की तरफ प्रतिबंधित रहेगा। यह मेफेयर तिराहा, सुभाष चौराहा, अल्का तिराहा, डनलप तिराहा, सिकंदरबाग चौराहा, ग्रीन कॉरिडोर होकर जा सकेगा। – चारबाग से महानगर, गोमतीनगर की ओर जाने वाला सामान्य यातायात बलिंग्टन चौराहा से बाएं अशोक लाट चौराहा होते हुए सुभाष चौराहा, हनुमान सेतु होकर जा सकेगा।

रायन इंटरनेशनल स्कूल, चेंबूर ने फिर से रचे शैक्षणिक उत्कृष्टता के नये प्रतिमान

मुंबई, 1 मई। मुंबई के प्रमुख शिक्षा संस्थान रायन इंटरनेशनल स्कूल, चेंबूर ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए आईसीएसई परीक्षा में अपने विद्यार्थियों की असाधारण उपलब्धियों की बदौलत शैक्षणिक उत्कृष्टता के नये प्रतिमान रचते हुए एक बार फिर से शानदार सफलता का परचम लहराया है।

यह जानकारी देते हुए रायन इंटरनेशनल स्कूल की वरिष्ठ शिक्षिका तथा मुंबई की सुपरिचित साहित्यकार श्रीमती प्रमिला शर्मा ने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 की दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में रायन इंटरनेशनल स्कूल, चेम्बूर का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा है। परिणाम घोषित होने पर विद्यालय में समारोहपूर्वक खुशियाँ मनाईं गईं। उन्होंने बताया कि रायन इंटरनेशनल स्कूल, चेंबूर ने हाल ही में हुई परीक्षाओं में 100% रिजल्ट पाकर गर्व महसूस किया है, जो एकेडमिक एक्सीलेंस के उसके सफर में एक और मील का पत्थर है। उन्होंने बताया कि यह शानदार उपलब्धि स्कूल के होलिस्टिक एजुकेशन, डिसिप्लिन्ड लर्निंग और लगातार एकेडमिक सपोर्ट के लिए पक्के कमिटमेंट को दिखाती है। मेधावी और सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों के इस ग्रुप को लीड करते हुए अनन्या श्रीकांत ने शानदार 99.40% हासिल किये। उसके बाद स्वरा प्रशांत शिंदे ने 98.60% अंक प्राप्त किये। उन्होंने कहा कि स्कूल को ऋषभ बनर्जी, कविश अमित परमार और मानित हेमल गांधी के शानदार परफॉर्मेंस पर भी बहुत गर्व है, जिन्होंने 97 % अंक स्कोर करके खुद को टॉप अचीवर्स में शामिल किया है। यह ओवर ऑल रिजल्ट एनालिसिस स्कूल के मजबूत एकेडमिक परफॉर्मेंस को बखूबी दिखाता है। उन्होंने बताया कि कुल 14 स्टूडेंट्स ने 95% से ज्यादा स्कोर किया, जबकि 64 स्टूडेंट्स ने 85% और 94% के बीच स्कोर किया। इसके अलावा, 48 स्टूडेंट्स ने 75% से 84% तक मार्क्स हासिल किए, और 15 स्टूडेंट्स ने 60% से 74% के बीच स्कोर किया। खास बात यह है कि किसी भी स्टूडेंट ने 60% से कम स्कोर नहीं किया, जो इंस्टीट्यूशन के लगातार बेहतरीन एकेडमिक स्टैंडर्ड को दशार्ता है। एग्जाम देने वाले कुल स्टूडेंट्स की संख्या 141 थी। उन्होंने कहा कि यह शानदार कामयाबी स्टूडेंट्स की लगन और कड़ी मेहनत का पुख़्ता सबूत है। साथ ही यह स्कूल की बहुत ही समर्पित फैकल्टी की लगातार कोशिशों को भी दिखाता है, जिनके गाइडेंस और मेंटरशिप ने इन सफलताओं को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। उनका मानना है कि माता- पिता से लगातार हिम्मत और सपोर्ट ने इस कामयाबी को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि हमारे छात्र-छात्राओं की सफलता हमारी सम्माननीय प्रबंधन टीम के अथक प्रयासों और समर्पण का भी प्रमाण है। विद्यार्थियों की प्रतिभा को पोषित करने में दूरदर्शी नेतृत्व और अटूट समर्थन के लिए अध्यक्ष डॉ. ए. एफ. पिंटो और प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो का योगदान अतुलनीय रहा है। विद्यालय के चेयरमैन ने सभी विद्यार्थियों को बधाइयाँ देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ प्रकट की हैं। उन्होंने कहा कि चेंबूर के रायन इंटरनेशनल स्कूल में, हम युवा दिमागों को न केवल एकेडमिक रूप से बल्कि कैरेक्टर और वैल्यूज में भी बेहतरीन बनाने में यकीन रखते हैं।

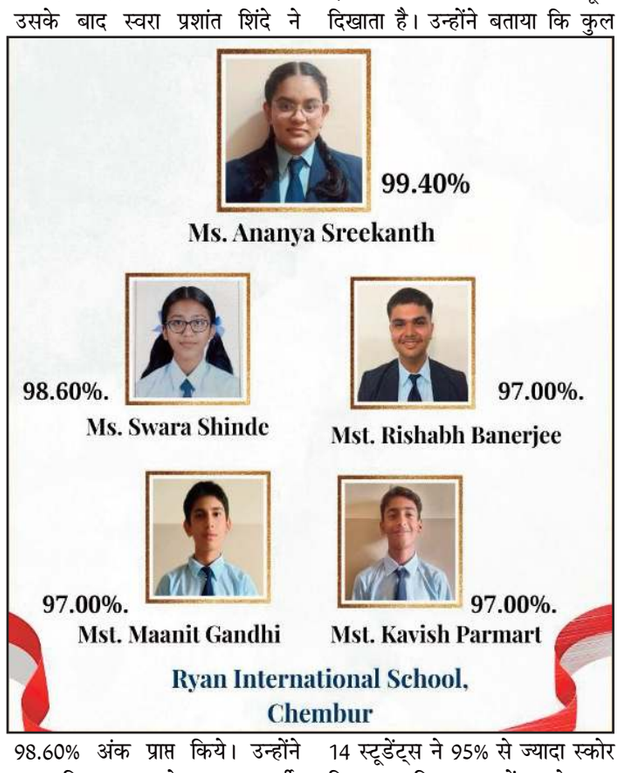

₹5 तक पेट्रोल-डीजल और ₹50 घरेलू एलपीजी बढ़ोतरी के संकेत? भारत में ईंधन होगा महंगा?

(एजेंसी)।

देश के करोड़ों वाहन मालिकों, घरेलू गैस उपभोक्ताओं और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के लिए चिंता की खबर। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में ₹4 से ₹5 प्रति लीटर और घरेलू 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर में ₹40 से ₹50 तक की बढ़ोतरी का गंभीर संकेत मिल रहा है। अगर यह फैसला हो गया, तो यह लगभग चार साल बाद ईंधन कीमतों में पहली बड़ी वृद्धि होगी। 2022 के बाद से पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतें लगभग स्थिर रहीं थीं।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के हवाले से सुर्खियों में आए। इसके बाद, सोशल मीडिया में खलबली मच गई है। आज 1 मई 2026 को कीमतें अभी भी स्थिर हैं, लेकिन तेल कंपनियों का घाटा बढ़ने और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते सरकार 5-7 दिनों के अंदर अंतिम निर्णय ले सकती है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया कि भारत इस संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन आम आदमी के बजट पर असर पड़ना तय है...

देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आज अपरिवर्तित हैं:

दिल्लीः पेट्रोल ₹94.77/लीटर, डीजल ₹87.67/लीटर

मुंबईः पेट्रोल ₹103.54/लीटर, डीजल ₹90.03/लीटर

कोलकाताः पेट्रोल ₹105.45/लीटर

चेन्नईः पेट्रोल ₹101.23/लीटर

घरेलू एलपीजी (14.2 किलो) की कीमत दिल्ली-मुंबई में ₹912-913 के आसपास है। हालांकि, 1 मई को भारत ने कमर्शियल छढऋसिलेंडर की कीमतों में ₹994 की भारी बढ़ोतरी की घोषणा की। इससे अब कमर्शियल सिलेंडर की दिल्ली में कीमत ₹3,071.50 हो गई है। पहले ये ₹2078.50 में मिल रहा था। मतलब साफ है कि रेस्टोरेंट, सड़क किनारे के ढाबे, कैटरर्स, बेकरी और क्लाउड किचन, छोटे व्यवसायों के उस अदृश्य नेटवर्क में चिंता की लहर दौड़ गई है, जो हर दिन भारतीयों का पेट भरता है।

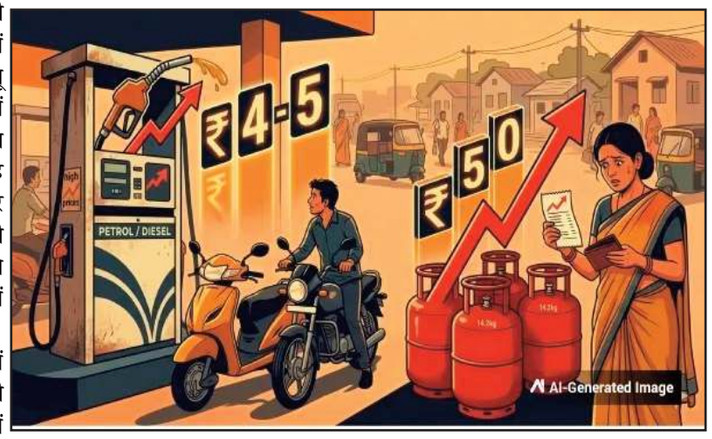

क्यों आ रहा है बढ़ोतरी का संकेत? पश्चिम एशिया तनाव ने बढ़ाई आग

मुख्य वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता युद्ध तनाव है। ईरान-इजरायल संघर्ष, हार्मुज जलडमरूमध्य में संभावित आपूर्ति व्यवधान और लंबे समय तक अस्थिरता की चिंता ने ब्रेंट क्रूड को $107-110 प्रति बैरल (कुछ रिपोर्ट्स में $126 तक) पर पहुंचा दिया है। भारत अपनी 85% कच्चे तेल की जरूरत आयात पर निर्भर है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों का सीधा असर पड़ रहा है।

तेल विपणन कंपनियां (IOC, BPCL, HPCL) भारी घाटे में हैं - पेट्रोल पर ₹14-24 प्रति लीटर और डीजल पर ₹18-100 प्रति लीटर का नुकसान। खुदरा कीमतें नहीं बढ़ने से उनकी आय प्रभावित हो रही है। सरकार पर सब्सिडी और टैक्स छूट का बोझ बढ़ रहा है। सूत्र बताते हैं कि आंतरिक विचार-विमर्श चल रहा है। सरकार तेल कंपनियों के दबाव को कम करना चाहती है, लेकिन मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित रखना है।

भारत की मजबूत रणनीति - 'ऊर्जा सुरक्षा का ओएसिस'

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक संकटों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा-

आयात विविधीकरणः पहले भारत 27 देशों से तेल आयात करता था, अब यह संख्या 40 हो गई है। इससे सप्लाई का जोखिम कम हुआ।

एलपीजी उत्पादन में 60% बढ़ोतरीः रिफाइनरियों को निर्देश दिए गए। उत्पादन 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गया।

'ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा': सरकार, कंपनियां और अंतरराष्ट्रीय सप्लायर्स का समन्वित प्रयास। संकट के समय भी सप्लाई चेन बरकरार रही।

तेल कंपनियों ने नुकसान उठायाः अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने पर भी कंपनियों ने घाटा सहा ताकि आम उपभोक्ता पर बोझ न पड़े।

33 करोड़ घरों में एलपीजी सप्लाईः घरेलू किचन पर कोई असर नहीं। कमर्शियल एलपीजी अब संकट से पहले के स्तर का 70% पहुंच चुकी है।

रोजगार से जुड़े सेक्टरों को प्राथमिकताः स्टील, ऑटो, टेक्सटाइल, केमिकल और प्लास्टिक उद्योगों को गैस उपलब्ध कराई जा रही है।

पुरी ने कहा कि दुनिया जब-जब तेल संकट में फंसी, भारत ने पहले से तैयारी करके हालात संभाले। हम ऊर्जा सुरक्षा के मामले में 'ओएसिस' बने हुए हैं।

दूसरी ओर पाकिस्तान में स्थिति भयावह है। IMF दबाव में सरकार ने पेट्रोल को ढडफ 399.86 प्रति लीटर और डीजल को PKR 399.58 प्रति लीटर कर दिया है। यानी ₹400 पार। हाल ही में पेट्रोल में ढडफ6.51 और डीजल में PKR 19.39 की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें, पैनिक बाइंग और आम लोगों में आक्रोश है। भारत की तुलना में पाकिस्तान की स्थिति दिखाती है कि हमारी रणनीति कितनी मजबूत है।

आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा?

अगर बढ़ोतरी हुई तोः

दैनिक कम्यूटरः 50 लीटर टैंक भरने वाले को महीने में ₹250-300 अतिरिक्त खर्च।

ट्रांसपोर्ट और सामानः ट्रक-बस किराया बढ़ेगा, सब्जी-दूध-फल की कीमतें 2-5% तक चढ़ सकती हैं।

घरेलू LPGः ₹50 बढ़ोतरी पर सालाना 12 सिलेंडर भरने वाले परिवार को ₹600 ी७३१ं बोझ।

मुद्रास्फीतिः खासकर ग्रामीण और मध्यम वर्ग पर दबाव बढ़ेगा।

सरकार का संतुलनः क्या होगा अगला कदम?

सरकार कई विकल्प तौल रही है - सीधी बढ़ोतरी, सब्सिडी बढ़ाना या एक्साइज ड्यूटी घटाना। फैसला 5-7 दिनों में आने की संभावना है। अधिकारी कहते हैं कि लक्ष्य है तेल कंपनियों का घाटा कम करना, लेकिन मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना।

भारत तैयार है, लेकिन सतर्कता जरूरी

यह फैसला सिर्फ पेट्रोल पंप या गैस सिलेंडर की कीमत नहीं, बल्कि पूरे अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति और आम बजट को प्रभावित करेगा। हरदीप सिंह पुरी की रणनीति साबित करती है कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है, आयात विविधीकरण, घरेलू उत्पादन बढ़ावा और उपभोक्ता सुरक्षा। पाकिस्तान की तुलना में हम बेहतर स्थिति में हैं।

फिलहाल सरकार ने अफवाहों पर शांति बनाए रखने की अपील की है। आम आदमी को सलाह है कि पैनिक बाइंग न करें, ईंधन बचत अपनाएं - कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और LPG का सही इस्तेमाल।

लापरवाही के बोझ से डूबा क्रूज? फ्री टिकट ने उलझाया आंकड़ों का गणित, 9 शव बरामद

(EªfZÖÁfe)Ü

मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम के बैक वॉटर में गुरुवार शाम हुआ क्रूज हादसा अब एक बड़ी मानवीय त्रासदी बन चुका है। 'नर्मदा क्वीन' नामक क्रूज तूफानी हवाओं और लहरों के बीच अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे ने जहां कई परिवारों को उम्र भर का गम दिया है, वहीं प्रशासन और पर्यटन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हादसे का शिकार हुई दिल्ली की संगीता कोरी ने मीडिया से बातचीत में जो बताया, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनके मुताबिक, शाम करीब 9 बजे जब क्रूज वापस लौट रहा था, तभी अचानक मौसम बिगड़ा। तूफानी हवाओं के साथ पानी क्रूज के अंदर भरने लगा।

लाइफ जैकेट के लिए छीना-झपटी

संगीता का आरोप है कि किसी भी यात्री को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी। जब क्रूज डूबने लगा, तब क्रूज स्टाफ ने स्टोर रूम से जैकेट निकालने की कोशिश की, जिससे यात्रियों के बीच जान बचाने के लिए छीना-झपटी मच गई।

लापरवाही और रेस्क्यू ऑपरेशन

शुरूआती जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद क्रूज का संचालन किया गया। स्थानीय लोगों ने चालक को रुकने का इशारा किया था, लेकिन अनुभवहीनता और लापरवाही के चलते उसने क्रूज नहीं रोका। फिलहाल, आगरा से आई सेना की टीम और NDRF हाइड्रोलिक मशीनों और गैस कटर से क्रूज को काटकर शवों की तलाश कर रही है।

टिकट और यात्रियों की संख्या का 'सस्पेंस'

हादसे के वक्त क्रूज पर सवार यात्रियों की सही संख्या को लेकर अब भी गहरा सस्पेंस बना हुआ है। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, क्रूज पर 29 पर्यटक और 2 क्रू मेंबर्स के होने की बात कही जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है।

चश्मदीदों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, क्रूज पर सवार लोगों की संख्या 40 के पार हो सकती है। इस अंतर की बड़ी वजह यह है कि क्रूज पर 10 से 12 छोटे बच्चे भी मौजूद थे, जिनका 5 साल से कम उम्र होने के कारण टिकट नहीं लगा था और उनका कोई हेड-काउंट (गिनती) नहीं किया गया। इसके अलावा, कुछ लोगों को बिना टिकट या 'फ्री' में बैठाए जाने की आशंका ने भी प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

पर्यटन विभाग के रिसॉर्ट से महज 100 मीटर की दूरी पर हुए इस हादसे के बाद अब पूरे संचालन तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। मौके पर मौजूद मंत्रियों ने स्पष्ट किया है कि क्षमता से अधिक भार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गंभीरता से जांच की जाएगी।

कितनी होती है एक क्रूज की क्षमता?

बरगी बांध में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साल 2006 से क्रूज का संचालन किया जा रहा है। यहां 'नर्मदा क्वीन' जैसे दो प्रमुख क्रूज संचालित होते हैं, जिनमें एक हाउस बोट और एक मिनी क्रूज शामिल है। आमतौर पर एक क्रूज की क्षमता लगभग 60 से 90 पर्यटकों की बताई जाती है। यहां एक व्यक्ति के टिकट की कीमत करीब 200 से 220 रुपये है। हालांकि, हादसे का शिकार हुए क्रूज में क्षमता से अधिक या बिना रिकॉर्ड के लोगों का सवार होना एक बड़ी लापरवाही के रूप में सामने आ रहा है, जिसकी वजह से बचाव दल को अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में कितने लोग लापता हैं।

मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं। घटनास्थल पर मौजूद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) की ओर से, जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

आधिकारिक आंकड़ेः मृतक, लापता और जीवित बचे लोगों की लिस्ट

1. मृतकों की लिस्ट (पुष्टिः 06) नीतू सोनी (उम्र 43), निवासीः जबलपुर, सोभाग्यम अलागन (उम्र 42), निवासीः तमिलनाडु, मधुर मैसी (उम्र 62), निवासीः दिल्ली, काकुलाझी (उम्र 38), निवासीः खमरिया, रेशमा सैय्यद (उम्र 66), शमीम नकवी (उम्र 66)

2. लापता व्यक्तियों की लिस्ट (संख्याः 09), तमिल (उम्र 5), पिताः कामराज, विराज सोनी (उम्र 6), मयूरम (उम्र 9), पूनम थापा (उम्र 7), ज्योति श्रीवास (उम्र 34), पतिः मनोज श्रीवास, त्रिशान/जहान (उम्र 4), पिताः प्रदीप मैसी, प्रदीप मैसी, मरिना मैसी, पतिः प्रदीप मैसी, कामराज (उम्र 39)

3. सकुशल बचे जीवित व्यक्तियों की सूची (कुलः 24), राखी सोनी (35 वर्ष), विक्की सोनी (विकास सोनी) (45 वर्ष), समृद्धि सोनी (18 वर्ष), इनिया (कल्र८) (12 वर्ष), आराध्या सोनी (12 वर्ष), मोहित नामदेव (23 वर्ष), महेश पटेल, छोटे लाल गौड़ (38 वर्ष), अनामिका सोनी (47 वर्ष), रियाज हुसैन (72 वर्ष), के. पवीथारन (10 वर्ष), मनोज श्रीवास (40 वर्ष), अंशिका, तनिष्क (11 वर्ष), तनिष्का (10

एआई बना हेल्थ सेक्टर का नया गेमचेंजर, रेयर डिज़ीज़ की पहचान में चिकित्सकों से भी आगे, रिसर्च में दावा

(एजेंसी)।

आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी (AI) अब डॉक्टरों को भी टक्कर देती दिख रही है। मरीज की बीमारी पहचानने से लेकर इमरजेंसी में इलाज संभालने तक यह कई कामों में डॉक्टरों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है या कर सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साइंस में पब्लिश हुई एक रिसर्चमें पाया गया कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी कई मामलों में डॉक्टरों के बराबर या उनसे बेहतर काम कर सकती है।

इससे साफ है कि आने वाले समय में इलाज के तरीके में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना नया सिस्टम पेश किया है जो मुश्किल बीमारियों की पहचान में काफी मददगार बताया जा रहा है।

इमरजेंसी केस में भी अक रहा आगे

OpenAI का advanced AI मॉडल अब इमरजेंसी रूम में भी मरीज की हालत समझने में बेहतर काम कर रहा है। अक मरीजों के लिए जरूरी टेस्ट सुझाने से लेकर पूरे इलाज को संभालने में मदद कर रहा है। कई मामलों में अनुभवी डॉक्टरों के बराबर या उनसे बेहतर भी रिजल्ट दे चुका है।

रिसर्च में इस मॉडल को बोस्टन के एक अस्पताल के 76 इमरजेंसी केस पर इस्तेमाल किया गया। इसे तीन स्टेप में परखा और टेस्ट कियआ गया है। शुरूआत में मरीज की जांच, डॉक्टर से पहली मुलाकात और फिर मरीज को वार्ड या कव में भेजने तक दो अलग-अलग डॉक्टरों ने बिना यह जाने कि जवाब अक का है या इंसान का इसका मूल्यांकन किया और पाया कि अकहर स्टेप में डॉक्टरों के बराबर या उनसे बेहतर रहा है।

अक ने सिर्फ केस स्टडी में ही नहीं बल्कि कम जानकारी और मुश्किल हालात में भी बीमारियों को पहचानने में अच्छा काम किया है। पुराने और जटिल केस जो कई सालों से टेस्ट के लिए इस्तेमाल होते आ रहे हैं, उनमें भी अक ने अच्छा रिजल्ट दिया है।

माइक्रोसॉफ्ट का नया अकसिस्टम क्या है?

माइक्रोसॉफ्ट का नया अकसिस्टम टअक-ऊ७ड एक एडवांस टूल है जिसे मुश्किल बीमारियों की पहचान के लिए तैयार किया गया है और टेस्ट में इसने लगभग 85.5% मामलों में सही नतीजे दिए जबकि डॉक्टरों का स्कोर करीब 20% रहा।

यह सिस्टम एक अकेला अक नहीं है, बल्कि कई अकमॉडल की टीम की तरह काम करता है। जहां अलग-अलग AI मिलकर सवाल पूछते हैं, संभावित बीमारी पर चर्चा करते हैं, गलतियों को पकड़ते हैं और सही जांच चुनते हैं। इसे 'चेन ऑफ डिबेट'कहा जाता है।

इस तरीके से अक न सिर्फ ज्यादा सही डायग्नोसिस करता है बल्कि कम और जरूरी टेस्ट चुनकर खर्च भी कम करता है। हालांकि यह अभी सिर्फ रिसर्च स्तर पर है और अस्पतालों में इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं है इसके लिए आगे और टेस्टिंग, सेफ्टी चेक और सरकारी मंजूरी लेनी होगी।

क्या AI बन जाएगी नया डॉक्टर?

स्टडी के राइटर अर्जुन मनराई के मुताबिक यह रिसर्च सिर्फ लिखित जानकारी पर आधारित थी जबकि असली इलाज इससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। असल में डॉक्टर मरीज से सीधे बात करते हैं उसकी पूरी समस्या और लक्षण समझते हैं,- rÔy और ECG जैसी रिपोर्ट देखते हैं और मरीज की भावनाओं व हालात को भी ध्यान में रखते हैं कई बार इलाज सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर नहीं बल्कि अनुभव और समझ से तय किया जाता है। जो अभी AI पूरी तरह नहीं कर सकता।

AI के पास जानकारी को तेजी से समझने और सुझाव देने की ताकत जरूर है लेकिन इंसानों जैसा अनुभव,भावनाओं और स्थिति के हिसाब से फैसला लेने की समझ अभी सीमित है। इसलिए इलाज के मामले में अंतिम फैसला हमेशा डॉक्टर ही लेते हैं जबकि अक एक असिस्टेंट के तौर पर काम करता है जो डॉक्टर को सही दिशा में मदद देता है।

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अचानक बेहोश हुए, लखनऊ मेदांता अस्पताल में भर्ती, पार्टी कार्यकताओं की जुटी भीड़

(एजेंसी)।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय को मेदांता लखनऊ अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है.

(एजेंसी)।

लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय की तबीयत अचानक बिगड़ने से राजनीतिक हलकों में चिंता का माहौल बन गया. शुक्रवार शाम वे अपने आवास पर थे, तभी अचानक उन्हें असहजता महसूस हुई और कुछ ही देर में वे बेहोश हो गए. प्राथमिक जानकारी के अनुसार उनके शरीर में सोडियम का स्तर कम होने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई.

अजय राय की हालत स्थिर लेकिन निगरानी में

घटना के तुरंत बाद परिजनों और सहयोगियों ने उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल ले जाया, जहां उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया. अस्पताल प्रशासन के अनुसार डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है और जरूरी मेडिकल जांचें की जा रही हैं. फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उन्हें अभी डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.

गुरुवार से ठीक महसूस नहीं कर रहे थे अजय राय

पार्टी सूत्रों के मुताबिक इससे पहले दिन में अजय राय एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे. कार्यक्रम के दौरान ही उन्हें हल्की परेशानी महसूस हुई थी, लेकिन बाद में शाम को उनकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई. बेहोश होने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला लिया गया, जिससे समय रहते इलाज शुरू हो सका.

डॉक्टरों ने क्या बताया

डॉक्टरों का कहना है कि शरीर में सोडियम का स्तर कम होना कई बार चक्कर आना, कमजोरी और बेहोशी जैसी स्थितियां पैदा कर सकता है. ऐसे मामलों में तुरंत चिकित्सकीय देखभाल बेहद जरूरी होती है. फिलहाल अजय राय की सभी जरूरी जांचें की जा रही हैं, जिसके बाद उनकी सेहत को लेकर और स्पष्ट जानकारी सामने आएगी.

अजय राय के बारे में

अजय राय पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम हैं. वे वाराणसी से विधायक रह चुके हैं और साल 2016 में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे. इसके बाद से वे राज्य में कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं.

साल 2023 में उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था. उस समय पार्टी राज्य में अपनी संगठनात्मक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी. अजय राय को यह जिम्मेदारी ऐसे समय में मिली, जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने आधार को दोबारा खड़ा करने की रणनीति पर काम कर रही थी.

फिलहाल पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, वहीं डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.

चुनाव में क्यों पिछड़ रही टीएमसी? एग्जिट पोल में छिपे वो 5 मुद्दे जिन्होंने बदल बंगाला का मूड!

(एजेंसी)।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? 2026 के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल के नतीजे तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मैटराइज के जारी किए गए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने राज्य की सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। सर्वे के मुताबिक, राज्य की 294 सीटों वाली विधानसभा में सत्ता की चाबी दीदी के हाथ से खिसकती नजर आ रही है।

मैटराइज ने बंगाल में टीएमसी को 125 से 140, भाजपा को 146 से 161 और अन्य को 06 से 10 सीटों मिलने का अनुमान लगाया है। हालांकि मैटराइज ने ये एग्जिट पोल 68,750 के सैंपल साइज पर किए हैं। जिसमें महिला 21,313 और पुरुष 33,688 शामिल हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि बंगाल के अलग-अलग क्षेत्रों, महिला-पुरुष वोटर्स और बड़े मुद्दों ने इस बार क्या कहानी बुनी है।

बंगाल का ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड: किसे कितनी सीटें और वोट?

एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि भाजपा इस बार बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करती दिख रही है। ओवरऑल सीट शेयर की बात करें तो भाजपा को 146-161 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि TMC+ को 125-140 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खाते में 06-10 सीटें जा सकती हैं।

वोट शेयर के मामले में भी भाजपा बाजी मारती दिख रही है। भाजपा को 42.5% वोट मिलने का अनुमान है, वहीं TMC+ को 40.8% वोट मिल सकते हैं। अन्य दलों को करीब 16.7% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई गई है।

यह सर्वे 23 अप्रैल से 29 अप्रैल 2026 के बीच 68,750 लोगों के रैंडम सैंपल के आधार पर किया गया है, जिसमें त्रुटि की संभावना +/- 3% है।

चुनावी मुद्दे: किन वजहों से बदला बंगाल का मूड?

मैटराइज के एग्जिट पोल डेटा के मुताबिक, इस बार बंगाल का चुनाव केवल भावनाओं पर नहीं, बल्कि ठोस जमीनी मुद्दों पर लड़ा गया है। अगर हम प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण करें, तो तस्वीर कुछ इस तरह उभरती है।

बेरोजगारी (14%): युवाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता रोजगार रही।

चुनाव में हिंसा (13%): बंगाल चुनाव में होने वाली हिंसा एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी।

अवैध घुसपैठ (12%): सीमावर्ती इलाकों में यह मुद्दा प्रभावी रहा।

सरकार से नाराजगी (12%): सत्ता विरोधी लहर ने भी अपना असर दिखाया।

भ्रष्टाचार (10%): घोटालों के आरोपों ने सरकार की छवि पर असर डाला।

अन्य मुद्दों में महिला सुरक्षा (7%), महंगाई (5%) और धार्मिक ध्रुवीकरण (5%) शामिल रहे।

दीदी के राज में 'मुद्दों' की राजनीति और बदलता बंगाल

बंगाल की राजनीति को पिछले 25 सालों से करीब से देखें तो पता चलता है कि दीदी (ममता बनर्जी) का करिश्मा आज भी बरकरार है, लेकिन उनके इस कार्यकाल में 'मुद्दे' अब नारों से ज्यादा भारी पड़ने लगे हैं। सर्वे में 14% बेरोजगारी और 10% भ्रष्टाचार का आंकड़ा मामूली नहीं है। याद कीजिए स्कूल सेवा आयोग (SSC) घोटाला, जिसने बंगाल के मध्यम वर्ग के भरोसे को हिलाकर रख दिया। जब एक आम बंगाली परिवार का बच्चा अपनी मेहनत के बजाय 'सिस्टम की धांधली' के कारण पिछड़ता है, तो वही गुस्सा ईवीएम (EVM) में निकलता है।

रही बात महिला सुरक्षा (7%) की, तो 'संदेशखाली' जैसी घटनाओं ने ममता बनर्जी की उस 'महिला रक्षक' वाली छवि को कड़ी चुनौती दी है, जो उन्होंने 'लक्ष्मी भंडार' जैसी योजनाओं से बनाई थी। बंगाल की राजनीति में 'महिला वोट बैंक' दीदी का सबसे मजबूत किला रहा है, लेकिन जब सुरक्षा पर आंच आती है, तो 44% महिला वोट शेयर के बावजूद भाजपा का 41% तक पहुंच जाना एक बड़ा रेड फ्लैग है।

वहीं चुनाव में हिंसा (13%) अब बंगाल की पहचान बनती जा रही है, जो दुखद है। पंचायतों से लेकर विधानसभा तक, खून-खराबा मतदाताओं को डराने के बजाय अब उनमें 'बदलाव' की जिद पैदा कर रहा है। 12% लोगों का 'अवैध घुसपैठ' को मुद्दा मानना बताता है कि सीएए (CAA) और एनआरसी (NRC) जैसी बहसें सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने वोटर्स के मन में घर कर लिया है। कुल मिलाकर, दीदी के इस टर्म में कल्याणकारी योजनाएं एक तरफ हैं और प्रशासनिक विफलताओं का बोझ दूसरी तरफ- और एग्जिट पोल के नतीजे इसी खींचतान की गवाही दे रहे हैं।

उत्तर बंगाल: भाजपा का अभेद्य दुर्ग?

उत्तर बंगाल (कूचबिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा) में भाजपा का दबदबा बरकरार रहने के संकेत हैं। यहां की कुल 54 सीटों में से:

भाजपा: 30-33 सीटें (43.8% वोट शेयर)।

TMC+: 15-18 सीटें (41.7% वोट शेयर)।

अन्य: 04-07 सीटें (14.5% वोट शेयर)।

यहां भाजपा का मजबूत वोट आधार टीएमसी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।

दक्षिण बंगाल: दीदी के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश

दक्षिण बंगाल, जिसे टीएमसी का सबसे मजबूत किला माना जाता है, वहां इस बार कांटे की टक्कर दिख रही है। इस क्षेत्र में मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा, हुगली और मेदिनीपुर जैसे जिले शामिल हैं। यहां की 183 सीटों का अनुमान कुछ ऐसा है:

TMC+: 88-98 सीटें (44.6% वोट शेयर)।

भाजपा: 80-90 सीटें (42.1% वोट शेयर)।

अन्य: 04-06 सीटें (13.3% वोट शेयर)।

भले ही यहां टीएमसी आगे दिख रही है, लेकिन भाजपा ने सीटों के मामले में फासले को काफी कम कर दिया है।

राढ़ बंगाल: बराबरी की जंग

पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूम और बर्धमान जैसे जिलों वाले राढ़ क्षेत्र की 57 सीटों पर मुकाबला लगभग बराबरी का है।

TMC+: 26-32 सीटें (43.7% वोट शेयर)।

भाजपा: 25-30 सीटें (42.4% वोट शेयर)।

अन्य: 00-02 सीटें (13.9% वोट शेयर)।

यह क्षेत्र तय करेगा कि सत्ता का संतुलन किस तरफ झुकेगा।

▶ जेंडर गेम: पुरुषों की पसंद भाजपा, महिलाओं का भरोसा अब भी दीदी पर?

वोटिंग पैटर्न में जेंडर का बड़ा रोल नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक...

पुरुष मतदाता: भाजपा पुरुषों की पहली पसंद बनी हुई है। करीब 44% पुरुष वोट भाजपा को, जबकि 40% टीएमसी को मिले हैं।

महिला मतदाता: टीएमसी की 'लक्ष्मी भंडार' जैसी योजनाओं का असर दिखता है। 44% महिलाओं ने टीएमसी का साथ दिया है, जबकि 41% महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया है।

बंगाल के लिए आए लगभग सभी एग्जिट पोल के मुताबिक, बंगाल में इस बार परिवर्तन की लहर दिख रही है। हालांकि अंतिम नतीजे क्या होंगे, यह तो चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगा, लेकिन आंकड़ों ने भाजपा के खेमे में उत्साह और टीएमसी के लिए चिंता की लकीरें जरूर खींच दी हैं।

बंगाल में बीजेपी की आहट से बांग्लादेश में भारी टेंशन! एग्जिट पोल के आंकड़ों की गूंज अब पड़ोसी देश की संसद में!

(एजेंसी)।

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी तेज हो गई है। 4 मई को आने वाले नतीजों से पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों ने वहां की संसद में हलचल मचा दी है।

खासकर बीजेपी की संभावित जीत और घुसपैठियों पर होने वाली कार्रवाई को लेकर बांग्लादेशी सांसद अख्तर हुसैन ने चिंता जताई है। उनका मानना है कि अगर बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता है, तो बांग्लादेश के सामने एक बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा हो सकता है।

बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन ने अपनी संसद में पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगर भारत के बंगाल प्रांत में बीजेपी की सरकार बनती है, तो वहां से बड़े पैमाने पर लोगों को वापस भेजा जा सकता है। हुसैन के अनुसार, यह स्थिति बांग्लादेश के लिए एक गंभीर 'रिफ्यूजी संकट' पैदा कर देगी। यह बयान दिखाता है कि भारतीय चुनाव के नतीजे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, खासकर पड़ोसी देशों की राजनीति को कैसे प्रभावित कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में बीजेपी को मजबूत स्थिति में दिखाया गया है। 'टुडेज चाणक्य' जैसी एजेंसियों ने बीजेपी को 192 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि सत्ताधारी टीएमसी 100 सीटों के आसपास सिमटती दिख रही है। पहली बार कई सर्वे एजेंसियां बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने की संभावना जता रही हैं। इन आंकड़ों ने ही बांग्लादेशी नेताओं के बीच डर और चर्चा का माहौल पैदा किया है।

घुसपैठ का मुद्दा और बीजेपी का रुख

भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में 'घुसपैठ' को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी सांसद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह घुसपैठ रोकने की दिशा में एक संकेत है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब धीरे-धीरे टीएमसी के मददगार और भारत विरोधी चेहरे सामने आ रहे हैं, जो बदलाव से डरे हुए हैं।

बांग्लादेश की 'नेशनल सिटिजन पार्टी' (NCP) अपने भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाती है। इस पार्टी का गठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्र नेताओं ने किया है। यह पार्टी न केवल भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देती है, बल्कि जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों के साथ भी इसके संबंध बताए जाते हैं। इनके नेताओं ने पहले भी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर विवादित टिप्पणियां की हैं, जो दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट पैदा करती हैं।

ईरान के पास तैनात होगी यूएस की सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल कितने की आती है- कौन बनाता है?

(एजेंसी)।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में डार्क ईगल मिसाइल तैनात करने पर विचार कर रहे हैं। यह हाइपरसोनिक हथियार अभी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन इसकी तैनाती से ईरान पर भारी दबाव बनेगा। ट्रंप के पास 1 मई तक कांग्रेस की मंजूरी लेने की डेडलाइन है। क्या यह कदम युद्ध को और भड़काएगा या शांति की राह खोलेगा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय ईरान के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध को लेकर भारी दबाव में हैं। उनके बयान और फैसले इस बात की सीधी गवाही दे रहे हैं जैसे- उनका सीजफायर का टाइम बढ़ाना, ईरान से बात करने न जाना आदि। इसकी वजह सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि अमेरिकी कानून भी है। 1973 के तहत अगर कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिलती, तो राष्ट्रपति को 1 मई तक अमेरिकी सेना को वापस बुलाना पड़ सकता है। यानी ट्रंप के पास फैसला लेने के लिए सीमित समय बचा है। इसी बीच खबर आ रही है कि ट्रंप अब मिडिल ईस्ट में अपनी सबसे ताकतवर में से एक मिसाइल डार्क ईगल तैनात कर रहे हैं।

पहली बार होगी डार्क ईगल की तैनाती

ईरान की ओर से शांति समझौते को लेकर नरम रुख नहीं दिखने के बाद ट्रंप प्रशासन ने अब मिडिल ईस्ट में अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल तैनात करने पर विचार शुरू कर दिया है। यह मिसाइल अभी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं मानी जाती, लेकिन अगर इसे तैनात किया गया तो यह पहली बार होगा जब अमेरिका इसे किसी एक्टिव वॉर जोन में इस्तेमाल करेगा। इससे अमेरिका हमला करे या नहीं लेकिन ईरान पर दबाव जरूर बनाना चाहता है।

क्या है डार्क ईगल? अमेरिका का महंगा सुपर वेपन

यह अमेरिकी सेना का लंबी दूरी वाला हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है। इसकी रेंज 2,776 किलोमीटर (1,725 मील) से ज्यादा बताई जाती है। इसकी असली क्षमताएं अभी तक सीक्रेट रखी गई हैं। इसकी खास बातें-

ध्वनि की गति से 5 गुना तेज उड़ान, ऊपरी वायुमंडल में यात्रा, हवा में दिशा बदलने की क्षमता, एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम

कितने का आती है डार्क ईगल मिसाइल?

इस मिसाइल सिस्टम को अमेरिकी कंपनी ने विकसित किया है। इसे खास तौर पर चीन और रूस जैसी शक्तियों की एडवांस एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। लागत-

एक मिसाइल: लगभग $1.5 करोड़ डॉलर, एक बैटरी (8 मिसाइल): लगभग $2.7 अरब डॉलर

अभी तक पूरी तरह तैयार भी नहीं

सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि डार्क ईगल को 2022 तक ऑपरेशनल होना था, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह तैयार घोषित नहीं किया गया है। इसका मतलब एक बिना तैयार हुआ हथियार अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है। इसी वजह से डिफेंस एक्सपर्ट इस पर सवाल उठा रहे हैं।

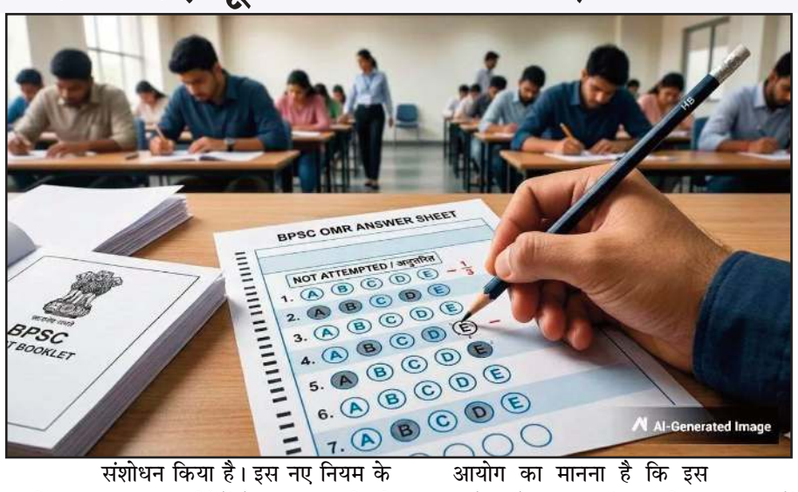

सेंटकॉम ने मांगी तैनाती, वजह भी गंभीर

अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी CENTCOM ने मिडिल ईस्ट में डार्क ईगल तैनात करने की इजाजत मांगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह परमरीशन ईरान के खिलाफ संभावित इस्तेमाल को ध्यान में रखकर किया गया है।

इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं-

प्रेसिजन स्ट्राइक मिसाइलों की कमी, मौजूदा लॉन्चर सिस्टम्स की सीमित पहुंच

यानी अमेरिका मानता है कि जो हथियार अभी इस्तेमाल हो रहे हैं, वे ईरान के बड़े मिसाइल ठिकानों को पूरी तरह निशाना बनाने के लिए काफी नहीं हैं।

मौजूदा हमले नाकाफी

अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अभी तक हुए हमले ईरान के बड़े और सुरक्षित सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं रहे हैं। इसी बीच अ७ङ्ग२ की रिपोर्ट में दावा किया गया कि उएठळउडट ईरान पर छोटे लेकिन बेहद ताकतवर हमलों की तैयारी कर रहा है। जिनमें टारगेट हो सकते हैं-

मिसाइल लॉन्च साइट्स, मिलिट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटजिक सप्लाई नेटवर्क, सरकारी इमारतें

बातचीत बंद, दोबारा शुरू होगी जंग?

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत ठप पड़ी हुई है। ट्रंप ने फारस की खाड़ी में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी जारी रखने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ तेहरान का कहना है कि पहले नाकेबंदी हटाओ फिर बातचीत होगी। यहीं से मामला और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि दोनों देश अपनी शर्तों से पीछे हटते नहीं दिख रहे।

फ्रूड्रेल्ल्ाि ऋ्र१ ङ्ग४

ढ' ढी३१ङ्ग' ढ१्रः ढ'२३ल्ल में टूटे सारे रिकॉर्ड, पेट्रोल के दाम पहुंचे 400 पार, डीजल-छढक्र ने भी मचाया हाहाकार

ढ' ढी३१ङ्ग' ढ१्रः ढ'२३ल्ल में टूटे सारे रिकॉर्ड, पेट्रोल के दाम पहुंचे 400 पार, डीजल-छढक्र ने भी मचाया हाहाकार

1 मई की डेडलाइन क्यों अहम है?

8 फरवरी को अमेरिका-इजरायल हमले के बाद ट्रंप ने 2 मार्च को कांग्रेस को सूचना दी थी। इसके बाद 60 दिन की कानूनी उलटी गिनती शुरू हुई। इस हिसाब से 2 मार्च से 1 मई तक 60 दिन पूरे होते हैं और 1 मई डेडलाइन है। अगर इसके बाद कांग्रेस इजाजत नहीं देती है तो अमेरिका को अपनी सेनाएं वापस बुलाना होंगी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं।

बीपीएससी ओएमआर शीट खाली छोड़ना अब पड़ेगा महंगा, आयोग ने बदल दिए मूल्यांकन के नियम, क्या है नया अपडेट?

(एजेंसी)।

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव किया है। अब आयोग की बहुविकल्पीय (MCQ) आधारित परीक्षाओं में उम्मीदवारों को हर सवाल का जवाब देना अनिवार्य होगा।

दरअसल, परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, अनुशासित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से आयोग ने प्रश्न पत्र के पैटर्न और मूल्यांकन पद्धति में संशोधन किया है। इस नए नियम के तहत, अभ्यर्थियों के पास अब किसी भी प्रश्न को 'अनदेखा' करने या खाली छोड़ने की सुविधा नहीं होगी।

आयोग का मानना है कि इस कदम से न केवल मूल्यांकन प्रक्रिया सटीक होगी, बल्कि परीक्षा के दौरान होने वाली संभावित गड़बड़ियों और ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

इढरए में अब 4 नहीं, होंगे 5 विकल्प

इढरउ की पुरानी व्यवस्था में अब तक केवल चार विकल्प (A, B, C और ऊ) होते थे, जिनमें से अभ्यर्थी सही उत्तर चुनते थे या सवाल छोड़ देते थे। लेकिन अब ओएमआर शीट पर पांचवां विकल्प 'ए' जोड़ा जा रहा है। यदि अभ्यर्थी को प्रश्न का उत्तर पता है, तो वह A, B, C या D में से सही विकल्प चुनेगा।

यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता, तो उसे अनिवार्य रूप से विकल्प 'ए' को रंगना होगा। इसका अर्थ होगा कि अभ्यर्थी ने इस प्रश्न को 'प्रयास नहीं किया'

खाली छोड़ा सवाल तो भुगतना होगा खामियाजा

नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नकारात्मक अंकन से जुड़ा है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रश्न के सामने पांचों विकल्पों (A से E तक) में से किसी को भी नहीं चुनता है, तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

किसी भी गोले को नहीं भरने पर उस प्रश्न को 'अनुत्तरित' माना जाएगा। ऐसे प्रत्येक खाली छोड़े गए प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/3 (एक-तिहाई) अंक काट लिए जाएंगे। यह दंड व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि कोई भी अभ्यर्थी ओएमआर शीट के किसी भी कॉलम को खाली न छोड़े।

पारदर्शिता और अनुशासन पर जोर

बीपीएससी के अनुसार, इस बदलाव के पीछे मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों में जवाबदेही तय करना है। अक्सर परीक्षाओं में खाली छोड़े गए कॉलमों को लेकर संशय बना रहता था, जिसे यह नया 'ए' विकल्प पूरी तरह समाप्त कर देगा। अब हर उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

यह नियम आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, जिससे चयन प्रक्रिया को और अधिक भरोसेमंद बनाया जा सके।

मेरठ से प्रयागराज तक नहीं लगेगा टोल! गंगा एक्सप्रेसवे पर कब तक फ्री में दौड़ेंगी गाड़ियां?

(एजेंसी)।

उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे और बहुप्रतीक्षित 'गंगा एक्सप्रेसवे' पर अब गाड़ियों ने फरार्टा भरना शुरू कर दिया है। प्रदेशवासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अगले 15 दिनों तक इस 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए आपको अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं निकालना होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'मजदूर दिवस' के अवसर पर प्रदेश की जनता को यह बड़ा तोहफा देते हुए 15 दिन तक फ्री सफर का ऐलान किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 29 अप्रैल को हरदोई से इस आधुनिक मार्ग का लोकार्पण किया था। आइए जानतें हैं गंगा एक्सप्रेसवे पर कब-से टोल देना होगा और दरें क्या होंगी?

कैबिनेट बैठक में टोल दरों का औपचारिक प्रस्ताव पास होने तक वाहन चालकों को यह राहत मिलती रहेगी। अधिकारियों के मुताबिक, टोल की वसूली 15 दिन बाद शुरू की जाएगी, जो सीधे आपके फास्टैग से कटेगी। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत इसका 'हाईटेक टोल सिस्टम' है, जहां एंट्री और एग्जिट को छोड़कर आपको कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। 120 किमी/घंटा की रफ्तार से आप महज 5 से 6 घंटे में मेरठ से प्रयागराज पहुंच जाएंगे।

ड्राइवर को झपकी आई तो सड़क खुद देगी चेतावनी

सिर्फ रफ्तार ही नहीं, गंगा एक्सप्रेसवे सुरक्षा के मामले में भी मिसाल है। लंबी दूरी की ड्राइविंग में अक्सर ड्राइवरों को नींद या झपकी आने का खतरा रहता है, जिससे हादसे होते हैं। इससे निपटने के लिए सड़क पर जगह-जगह 'रंबल स्ट्रिप्स' (उभरी पट्टियां) लगाई गई हैं। जैसे ही गाड़ी इन पर से गुजरेगी, एक कंपन पैदा होगा जो ड्राइवर को तुरंत अलर्ट कर देगा। साथ ही, देश में पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर हर 1 किमी पर सीसीटीवी और ट्रॉमा सेंटर की सुविधा दी गई है।

किस दिन से देना होगा टोल?

योगी सरकार द्वारा मजदूर दिवस (1 मई) को किए गए इस ऐलान के बाद, गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहन चालक 15 मई 2026 तक मुफ्त सफर का आनंद ले सकेंगे। इसके ठीक बाद, यानी 16 मई 2026 से एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की वसूली अनिवार्य रूप से शुरू हो जाएगी।

किसे कितना देना होगा टोल? (जरूरी जानकारी)

जब 15 दिनों का फ्री सफर खत्म होगा, तब वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तय की गई ये दरें लागू होंगी:

कार, जीप और हल्के वाहन: ₹1800 (लगभग ₹2.50 प्रति किमी)

बाइक और रजिस्टर्ड ट्रैक्टर: ₹905

बस और ट्रक: ₹5720

हल्के व्यावसायिक वाहन (मिनी बस): ₹2840

भारी मशीनरी (7 या अधिक एक्सल वाले वाहन): ₹11265 तक

यह एक्सप्रेसवे न केवल मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं और प्रयागराज समेत 12 जिलों को जोड़ेगा, बल्कि शाहजहांपुर में बनी 3.5 किमी लंबी हवाई पट्टी के जरिए आपात स्थिति में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए भी तैयार है।